बंदरगाहों की माल उतारने एवं चढ़ाने की क्षमता

1325. **श्री राम जेठमलानी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गत तीन वर्ष पूर्व उद्योग के उदारीकरण और उसका विश्व स्तर पर विस्तार करने के संबंध में लिए गए निर्णय के उपरांत भारतीय उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए भारतीय बंदरगाहों की माल उतारने और चढ़ाने की क्षमता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है ;

(ख) वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1993-94 के अंत में बंदरगाहों की अनुमानित क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान शुष्क बंदरगाहों की संख्या और उनकी क्षमता में वृद्धि की है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 और 1993-94 के अंत में इनकी संख्या और क्षमता कितनी-कितनी थी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पत्तन क्षमताओं में वृद्धि के लिए योजनाएं यातायात वृद्धि के रुख को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं । सभी महा-पत्तनों की कुल क्षमता 31-3-91 को 169.23 मि० टन और 31-3-94 को 173.04 मि० टन थी । आठवीं योजना-अवधि के अन्त तक इसके 237 मि० टन हो जाने की संभावना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार, सरकार ने 27 अंतर्देशीय कन्टेनर डिपुओं/कन्टेनर फ्रेट/स्टेशनों के लिए मंजूरी दे दी थी । तबसे, सरकार द्वारा 22 अतिरिक्त अंतर्देशीय कन्टेनर स्टेशनों/कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों के लिए मंजूरी दी गई है ।

River services between Calcutta and Dibrugarh

1326. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the routes on which the river/sea services are at present being operated by Central Inland Water Transport Corporation (CIWTC) and Shipping Corporation of India (SCI) for movement of cargo as well as passengers, route-wise details alongwith the details of passenger fares in various classes;

(b) whether it is a fact that Dibrugarh was a major river port of Assam till late fifties providing cheap goods transportation to the whole of upper Assam from Calcutta;

(c) whether it is also a fact that after the creation of Bangladesh, river services for carriage of heavy goods were resumed between Calcutta and Guwahati only;

(d) whether Government have any plans to start river services between Calcutta and Dibrugarh and thereby revive Dibrugarh river port; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JADISH TYTLER): (a) The routes on which the river services are at present being operated by the Central Inland Water Transport Corporation Ltd. (CIWTC) for movement of cargo between Calcutta and Dibrugarh, are indicated below:-

Calcutta-Pandu
Pandu-Calcutta
Calcutta-Karimganj
Karimganj-Calcutta
Calcutta-Bangladesh

Bangladesh-Calcutta

Assam-Bangladesh

Calcutta-Haldia

Haldia-Calcutta

Calcutta Internal Saugor Operations

Haldia-Budge Budge (POL)

The CIWTC do not operate any passenger service. The Shipping Corporation of India (SCI) do not operate any river services for cargo or passenger traffic between Calcutta and Dibrugarh.

(b) Prior to 1950, 150T to 250T steamers used to operate between Calcutta and Dibrugarh on regular basis. After the earth quake in 1950, the vessels were operated only upto Desangmukh as the terrain between Dibrugarh and Desangmukh became diffiult and bed raised up by over 3 metres.

(c) Regular service is being run by the CIWTC from Calcutta to Guwahati as per availability of cargo. The CIWTC has deck loading vessel for carriage of heavy over-dimensional cargo.

(d) and (e) A minimum of 2 m depth is being maintained by tre Inland Waterways Authority of India (IWAI) in the Dhubri-Guwahati stretch of the river Brehmaputra. The IWAI has a scheme to develop and maintain a minimum of 2 m depth in the Guwahati-Dibrugarh stretch and to develop a terminal with cargo handling facility at Dibrugarh, depending on the traffic demand.

निजी निवेशकों द्वारा सरकारी गारन्टी की मांग किया जाना

1327. **श्री सोमपाल** *

श्री अनन्त राम जायसवाल *

क्या जल-भूतलज परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश और विदेश में निजी निवेशकों ने सड़क निर्माण परियोजनाओं में निवेश करने के लिए सरकार से प्रति-गारंटी (काउंटर-गारन्टी) की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सड़क निर्माण का कार्य निजी कंपनियों को देने के विषय पर सरकार ने कोई अंतिम निर्णय लिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या है और उसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) निजी कंपनियों को यह कार्य किन शर्तों पर दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) (क) से (ङ)- सरकार, विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बी०ओ०टी० (बनाओ, चलाओ और स्तांतरित करो) के आधार पर शुल्क-आधारित सुविधाओं के निर्माण रखरखाव और प्रचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करने पर विचार कर रही है । तथापि, इस संबंध में नीति-संबंधी दिशा निर्देशों का अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इसलिए अभी इस स्तर पर स्थिति विनिर्दिष्ट कर पाना संभव नहीं है ।

Development of National Highway Projects

1328. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a press news-item captioned "Poor planning hits projects as reported in the Statesman dated 4th July, 1994;

(b) if so, whether the growth of vehicles on National Highways are increasing and the development of Highways is poor;